समावेशी वृद्धि हासिल करना : नए युग की चुनौती *

दुव्वुरी सुब्बाराव

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से माननीय थर्मन् षण्मुगरत्नम्, उप प्रधानमंत्री, सिंगापुर का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। श्री षण्मुगरत्नम् एल.के. झा स्मारक व्याख्यान का प्रारंभ कुछ ही समय पश्चात करेंगे।

2. स्वर्गीय डॉ. एल.के. झा के परिवार के सदस्यों - श्रीमती दीपिका महाराज सिंह, श्रीमती शारिका ग्लोवर और किरन ग्लोवर की इस सभागार में उपस्थिति से भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों की उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यहां पधारने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। साथ ही, अपना अमूल्य समय निकालकर इस व्याख्यान को सुनने आए हमारे सभी प्रतिष्ठित आमंत्रितगणों का भी हार्दिक स्वागत है।

डॉ. एल. के. झा

3. इतिहास में डॉ. एल.के. झा को भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित लोकसेवकों के रूप में याद किया जाएगा। आर्थिक प्रशासक होने के साथ ही बहुत सी प्रभावोत्पादक उपलब्धियाँ उनके नाम होने से उनका कैरियर उल्लेखनीय था। लोक सेवकों की बहुत सी पीढ़ियों के लिए वे एक आदर्श हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद 'एलके', जिस नाम से वे लोकप्रिय थे, अध्ययन के लिए ट्रिनिटी कॉलेज, लंदन गए, जहां उन्हें ए.सी. पिगॉस, जे.एम. कीन्स और डी.एच. रॉबर्टसन जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने का मौका मिला। उन्होंने 1936 में भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की। प्रारंभ में बिहार में काम करने के बाद 1942 में उन्हें भारत सरकार की सेवा के लिए स्थानांतरित किया गया जहां उन्होंने अनेक महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। प्रधानमंत्री के सचिव के रूप में महत्त्वपूर्ण काम करने के साथ उनका कैरियर समाप्त हुआ।

4. डॉ. झा ने जुलाई 1967 से मई 1970 तक की अवधि में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया जब हमारी अर्थव्यवस्था अपने सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही थी। देश खाद्य सुरक्षा की चिंताओं से घिरा हुआ था जिनका निवारण करने के लिए उठाए गए कदम 'हरित क्रांति' में परिणत हुए। गवर्नर झा ने इन कदमों को रूप देने में, अपने नेतृत्व के माध्यम से, भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रभावशाली संस्था बना दिया। समग्ररूप से अभावपूर्ण स्थिति होने से गरीबों की परेशानियों के परिणामस्वरूप गरीबी को कम करना सभी नीतियों का अतिमहत्त्वपूर्ण अंग बन गया। डॉ. झा के प्रबंधन के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक ने गरीबीरोधी बहुत सी नीतियाँ तैयार करने और उन्हें लागू करने में अपना योगदान किया।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपनी सेवाओं के बाद डॉ. झा ने अमरीका में भारत के राजदूत के रूप में तथा जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के रूप में सेवाएं दीं। वे बहुचर्चित ब्रैंट आयोग के भी सदस्य रहे जिसने उत्तर-दक्षिण सहयोग के लिए उपयुक्त समझौते का स्वरूप तैयार किया। आजकल दैनिक विचार-विमर्श में हम जिस वैश्विक सहयोग की बात करते हैं उसकी वैचारिक उत्पत्ति का श्रेय 1970 के दशक की ब्रैंट आयोग की रिपोर्ट को जाता है जिसमें डॉ. झा का योगदान था।

6. उनके नाम पर यह व्याख्यानमाला राष्ट्र के लिए बेहतरीन सेवाओं और बहुत नाजुक समय में भारतीय रिज़र्व बैंक को नेतृत्व प्रदान करने के लिए डॉ. झा के प्रति सम्मान दर्शाती है। इस शृंखला में अब तक 12 व्याख्यान हुए हैं। पिछला व्याख्यान गत वर्ष दिसंबर 2011 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मॉरिस ऑब्स्टफील्ड ने दिया था। आज की शाम, माननीय श्री षण्मुगरत्नम का व्याख्यान इस श्रृंखला का 13वां व्याख्यान होगा।

प्रख्यात वक्ता - श्री षण्मुगरत्नम्

7. माननीय श्री षण्मुगरत्नम् सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री होने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति के अध्यक्ष भी हैं। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति में धारित पद ने उन्हें वित्त और अर्थशास्त्र जगत के वैश्विक नेताओं के बीच उन्हें शीर्ष स्थिति में ला दिया है। उनका नेतृत्व हमें हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े वित्तीय संकट से उबारने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

8. श्री षण्मुगरत्नम् की बेहतरीन शैक्षिक पृष्ठभूमि रही है। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएस की उपाधि प्राप्त की है, उसके बाद हार्वर्ड से लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री भी हासिल की है। उत्कृष्ट

* 13वें एल.के. झा स्मारक व्याख्यान में 27 सितंबर 2012 को भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव द्वारा दिया गया स्वागत भाषण।

निष्पादन और नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें हार्वर्ड में ल्यूसिअस एन. लिताउर छात्रवृत्ति भी दी गई। बाद के उनके कैरियर में इस क्षमता का बढ़िया प्रभाव देखने को मिला।

9. श्री थर्मन के कैरियर की शुरुआत मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर से हुई जहां उन्होंने उस प्रतिष्ठित संस्था के मुख्य कार्यपालक के पद को सुशोभित किया। राजनीति में पदार्पण करने के लिए उन्होंने 2001 में उस पद को छोड़ दिया और शिक्षा, आर्थिक प्रशासन और जनबल जैसे विभिन्न मंत्रालयों का कार्य संभाला। वर्तमान में वे उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हैं।

10. समूह-20 और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष-विश्व बैंक की बैठकों सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर श्री षण्मुगरत्नम् को काम करते हुए देखने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। अपनी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता के लिए, तथा किसी विषय को तात्कालिकता के दबाव के बीच प्रस्तुत किए जाने पर भी उस विषय के व्यापक परिदृश्य को समझने की उनकी असाधारण योग्यता के कारण भी सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं। वैश्विकरूप से उन्हें एशिया की आर्थिक प्रतिष्ठा और आकांक्षा के मुख्य वार्ताकार के रूप में देखा जाता है।

समावेशी वृद्धि हासिल करना: नए युग की चुनौती

11. आज की शाम श्री षण्मुगरत्नम् 'समावेशी वृद्धि हासिल करना : नए युग की चुनौती' विषय पर व्याख्यान देंगे। एशिया के मूल्यों और प्रकृति की समझ के साथ व्यापक स्तर पर अंतराष्ट्रीय अध्ययन एवं अनुभव के दृष्टिकोणों के संयोग के कारण वे इस विषय पर चर्चा करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं।

12. भारत में हमारे लिए समावेशी वृद्धि निश्चित रूप से बहुत महत्त्व का विषय है किंतु मेरा मानना है कि यह विषय विश्व के सभी देशों, चाहे वे अमीर हों अथवा गरीब, के लिए भी महत्त्व का है। समावेशी वृद्धि की तलाश विकास के दौरान प्राप्त हुई इस महत्त्वपूर्ण शिक्षा से होती है कि अगर पिरामिड के निचले स्तर के लोग वृद्धि के लाभों से वंचित रह जाएं तो विकास बेमानी हो जाता है अथवा वास्तव में इसकी कोई वैधता नहीं रह जाती है।

13. किंतु लोगों का किसी भी तरह का मतैक्य इसी बिंदु पर भंग हो जाता है। इस आधारभूत वाक्य के बाद कि समावेशी वृद्धि अपेक्षित है, समावेशी वृद्धि किन घटकों से मिलकर बनती है - से लेकर इसे कैसे प्राप्त किया जाए और कायम रखा जाए - तक के लगभग प्रत्येक मामले और बारीकियों में विवादपूर्ण स्थिति है और अक्सर यह बहस का विषय होता है।

14. विकास अर्थशास्त्र की कई अन्य बहसों की तरह ही यह बहस भी ऐसी है जिसमें मितव्ययिता के नाम पर त्यौरियां चढ़ जाती हैं। एक ओर 'निचले स्तर तक अपने आप पहुँच' का सिद्धांत है जिसकी यह मान्यता है कि विकासजनित लाभ स्वयं ही निचले स्तर के लोगों तक पहुंच जाएंगे। 'निचले स्तर तक अपने आप पहुँच' की प्रक्रिया ऐसी है जिसे उसकी स्वाभाविक गति और मार्ग पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसे नीचे की ओर जबरदस्ती ले जाने से इसका विपरीत असर हो सकता है। इसके ठीक विपरीत सक्रियतावादी विचार है जिसके अनुसार 'निचले स्तर तक अपने आप पहुँच' का सिद्धांत बेकार की बात है तथा यह पुनर्वितरण नीतियों को विकास के प्रतिमान का अनिवार्य अंग बनाने के पक्ष में है, भले ही इसके लिए वृद्धि की गुणवत्ता और गति से समझौता करना पड़ेगा। जैसा कि हम सभी महसूस करते हैं, समावेशी वृद्धि एक गंभीर भावनात्मक मुद्दा है जिसके कारण यह अर्थशास्त्र से आगे बढ़कर राजनीतिक विमर्श और चुनावी मंचों तक पहुँच चुका है।

15. वैश्वीकरण के युग में समावेशी वृद्धि संबंधी बहस ने अंतरराष्ट्रीय स्वरूप भी ले लिया है जो स्वभाविक ही है। क्या संसार में ऐसी व्यवस्था टिकाऊ होगी जिसके तहत कुछ देश उन्नति करें और कुछ विकास में पीछे रह जाएं? यदि नहीं तो अमीर देशों और गरीब देशों की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए ? राष्ट्र राज्यों के प्रभुत्व वाले विश्व में हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त भूमि कैसे निर्मित करें?

16. समावेशी वृद्धि के बारे में सिर्फ उभरती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं ही चिंतित नहीं हैं। अमीर देशों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। पिछले वर्ष विश्वभर में बड़े पैमाने पर असंतोष दर्शाने वाले प्रदर्शन हुए। न्यूयार्क के जुक्कोटी पार्क में हुआ 'ऑक्युपाई द वाल स्ट्रीट' प्रदर्शन सबसे महत्त्वपूर्ण था और यह इस प्रकार का अकेला प्रदर्शन नहीं था। इस प्रदर्शन के अव्यवस्थित होने और इसकी मांग स्पष्ट न होने के बाद भी विश्वभर में होने वाले प्रदर्शनों का आधार एक साधारण किंतु शक्तिशाली विचार था कि अमीर लगातार अमीर नहीं होते रह सकते जबकि शेष लोग और गरीब होते जा रहे हों। इस सामूहिक रोष से यह संदेश मिला कि अगर वृद्धि समावेशी न हो तो इसके कारण भी अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।

17. इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि 13वें एल.के. झा स्मारक व्याख्यान में समावेशी वृद्धि की चुनौती विषय पर व्याख्यान देने के लिए आप सभी मेरे साथ श्री थर्मन् षण्मुगरत्नम् का स्वागत करें।